(b) and (c) To increase the forest cover, a massive programme of afforestation, Social & farm forestry under the 20 Point Programme is pursued vigorously with people's participation. During the Seventh Five Year period 8.8 million hectares were planted up against the target of 8.2 million hectares.

It is proposed to substantially expand the coverage of afforestation/ tree planting activities during the Eighth Five Year Plan, which is under finalisation.

Damage due to the leak of the oil tanker "Maersk Navigator"

185. SHRI VIREN J. SHAH:
MISS SAROJ KHAPARDE:
SHRI M. A. BABY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have made any spot assessment of damage on fish and marine life due to the oil leak from the oil tanker "Maersk Navigator" which met with an accident on January 21, 1993;

(b) if so, what has been its effect on the lives of tribals living on these Islands and a wide variety of fish and Marine life availablt in these areas; and

(c) what steps have been taken to control the leak and to ensure that the slick moved away from the Nicobar coast; the details?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The research vessel, 'Sagar Kanya', of the Department of Ocean Development with the scientists of National Institute of Oceanography, Goa, on board, has undertaken marine surveys to collect samples at the area of the oil spill. A second cruise will be conducted to study the long term effect on marine life. An assessment of damage to marine and tribals life and environment in monetary term can be made only after detailed scientific analysis.

(c) The following measures have been taken by the Coast Guard to tackle the oil spill and to minimise its effect on marine life in the region:—

(i) Continued monitoring of movement of damaged tanker and oil spill was undertaken using air and ship surveillance. The oil leakage from the tanker has already been plucked;

(ii) Combating the oil slick by aerial and ship spray of chemical dispersant;

(iii) The damaged tanker was ordered to be cleared of the Indian Exclusive Economic Zone waters as early as possible;

(iv) Water samples were collected from affected area for analysis; and

(v) The operations lasted from 22nd January, 1993 to 6th February, 1993. A complete sweep of the area was carried out to ensure that all remnants of the oil slicks were effectively neutralised.

Climatic Changes

186. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the report of inter-governmental panel on climatic change (IPCC) and its discrepancies between developed and developing world;

(b) if so, what action has been taken by Government to correct the IPCC report after Post-Rio Summit; and

(c) the details thereof and on the issue of sharing the burden of cost of reducing CO2 emission?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The various issues including the ones mentioned in the question are under discussion at the various IPCC-Meetings.

उत्तर प्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन

187. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन न हो।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन वाले मामलों में निर्णय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार लिया जाता है।

गुजरात में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

188. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे उद्योग अभी भी कार्यरत हैं ;

(ग) यदि हां, तो इनको कार्य करते रहने की मंजूरी देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कौन-कौन से उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) : जी, हां। सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठा रही है जिसके अनुसार 16 मई, 1981 को या उससे पहले तथा 16 मई, 1981 के पश्चात् (लेकिन 31 दिसम्बर, 1991 से पूर्व) स्थापित उद्योगों द्वारा क्रमशः 31 दिसम्बर, 1992 तथा 31 दिसम्बर, 1993 तक निर्धारित मानकों का पालन किया जाना अपेक्षित है। कार्यवाई को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 17 उद्योग श्रेणियों की शिनाख्त की गई है।

गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दोषी इकाइयों के विरुद्ध न्यायालय में मामले दायर करके कार्यवाई की है। चूंकि मामले लम्बित हैं, इसलिए दोषी उद्योग चल रहे हैं।

(घ) केन्द्र सरकार बड़े और मझौले उद्योगों की अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की 17 श्रेणियों में दोषियों की निगरानी कर रही है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि गुजरात में 212 इकाइयों में से 153 इकाइयां पूरी तरह से मानकों का पालन कर रही हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रयोजन के लिए स्थापित अपने कृत्यक बलों के द्वारा उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति की प्रगति की निगरानी कर रहा है।